

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2014/फाल्गुन 1, 1935

No. 413]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2014/PHALGUNA 1, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2014 सं. 70 (आर.ई.—2013)/2009—2014

विषय:- विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के अध्याय-5 में संशोधन।

का.आ. 493(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009—14 के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009—14 के पैरा 5.5.1 के उप—पैरा (ख) में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

2. उप-पैरा 5.5.1(ख) के बाद एक नया उप-पैरा (ग) शामिल किया जा रहा है। नया पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः 5.5.1(ग) जहाँ भी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को कारपोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) के तहत राहत प्रदान की जाती है तो ऐसे प्राधिकार पत्र धारक को 3 वर्षों (सीडीआर तंत्र/स्कीम के अनुमोदन की तारीख से) के लिए निर्यात दायित्व विस्तार की अनुमित दी जा सकती है। निर्यात दायित्व में ऐसे विस्तार के लिए कोई कंपोजिशन फीस नहीं लगेगी और यह प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैरा 5.11 के तहत उपलब्ध निर्यात दायित्व विस्तार, यदि कोई हो, प्रदान किए जाने के अतिरिक्त (और के बदले नहीं) होगा।

इस अधिसूचना का प्रभावः

संबंधित ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए 3 वर्षों के अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा सकती है यदि ऐसा प्राधिकार पत्र धारक कारपोरेट ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत राहत प्राप्त करता हो।

[फा. सं. 18 / 48 / एएम-14 / पी-5]

अनुप के. पूजारी, महानिदेषक, विदेश व्यापार

731GI/14

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2014

No. 70 (RE-2013)/2009-2014

Subject: Amendment in Chapter 5 of Foreign Trade Policy 2009-14

S.O.493(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes the following amendment in sub-para (b) of Para 5.5.1 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2009-14 with immediate effect:

2. A new sub-para (c) is being inserted after sub-para 5.5.1(b). The new para shall read as under:

5.5.1 (c) Wherever the holder of any EPCG Authorization is granted relief under Corporate Debt Restructuring (CDR), then such Authorization holder may be allowed EO extension of 3 years (from the date of approval of the CDR mechanism/scheme). Such extension in EO will not attract any Composition fee and will be in addition to (and not in lieu of) the granting of EO extension, if any, available under Para 5.11 of HBP v1.

Effect of this Notification:

Additional time of 3 years for fulfillment of EO may be allowed to the concerned EPCG Authorization holder, if such holder receives relief under Corporate Debt Restructuring mechanism.

[F. No. 18/48/AM-14/P-5]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade